



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2694]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2018/आषाढ़ 25, 1940

No. 2694]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2018/ASHADHA 25, 1940

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

का.आ. 3465(अ).—कावेरी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) को तारीख 2 जून, 1990 को अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ) तारीख 2 जून, 1990 द्वारा अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अंतरराज्यिक कावेरी नदी और उसकी नदी धाटी से संबंधित जल विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए गठित किया गया था ;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय, तारीख 05 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत कर दिया था ;

और पक्षकार राज्यों और केन्द्रीय सरकार, ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन तारीख 27 अप्रैल, 2007, 30 अप्रैल, 2007 और 3 मई, 2007 को उक्त अधिकरण को और निर्देश प्रस्तुत किए थे और अधिकरण को 3 मई, 2007 से एक वर्ष के भीतर एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण के अनुरोध पर, उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा 2 मई, 2018 तक बढ़ाया था ;

माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तामिलनाडु राज्य, कर्नाटक राज्य और केरल राज्य द्वारा, उनके जल आबंटन संबंधी अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध फाइल की गई 2007 की सिविल अपील संख्या 2453, 2007 की सिविल अपील संख्या 2454, 2007 की सिविल अपील संख्या 2456 में तारीख 16 फरवरी, 2018 और 18 मई, 2018 के अपने आदेश द्वारा अंतिम निर्णय दे दिया है और उक्त अधिकरण के अधिनिर्णय का अब माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 के निर्णय के साथ विलय हो गया है।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि मामले में उक्त अधिकरण को कोई और निर्देश करना आवश्यक नहीं होगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण को समाप्त करती है।

[फा. सं. 1/5/2015—बी. एम.]

संजय कुन्दू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2018

S.O. 3465(E).—Whereas, the Cauvery Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd June, 1990 vide notification number S.O. 437(E), dated the 2nd June, 1990 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Cauvery and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 5th February, 2007;

And whereas, the party States and Central Government made further references to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 27th April, 2007, the 30th April, 2007 and the 3rd May, 2007 and the Tribunal had to submit a further report within one year from the 3rd May, 2007;

And whereas, the Central Government has, on the requests made by the Tribunal, extended the period of submission of further report by the said Tribunal till 2nd May, 2018 vide notifications issued from time to time;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide its orders dated the 16th February, 2018 and the 18th May, 2018 has delivered final judgement in the Civil Appeals No. 2453 of 2007, 2454 of 2007, 2456 of 2007 filed by States of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala against the award of the said Tribunal on the allocation of water to them, and the Award of the said Tribunal has now merged with the Judgement dated the 16th February, 2018 of the Hon'ble Supreme Court.

And whereas, the Central Government is satisfied that no further reference to the said Tribunal in the matter would be necessary.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act, the Central Government hereby dissolves the said Tribunal.

[F. No. 1/5/2015-BM]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.